भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या – 369
दिनांक 20.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ब्राजील में जी-20 बैठक

*369. **श्री अरुण गोविलः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में आयोजित जी–20 बैठक में एक पूरा सत्र वैश्विक शासन के संस्थानों में सुधारों के लिए समर्पित था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जी-20 नेता इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए एकजुट होकर काम करने पर सहमत हुए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संगठन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या हाल ही में ब्राजील में आयोजित जी-20 बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा मजबूत हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश मंत्री
[डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर]

(क) से (घ): वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"ब्राजील में जी-20 बैठक" के संबंध में दिनांक 20.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 369 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित वक्तव्य।

18 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो जेनेरियो में रियो जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले दिन वैश्विक शासन संस्थानों के सुधार पर एक विशिष्ट पूर्ण सत्र आयोजित किया गया।

शिखर सम्मेलन में अनुमोदित जी20 रियो डी जेनेरियो नेताओं के घोषणापत्र में नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों में निहित एक पुनर्जीवित और सुदृढ़ बहुपक्षीय प्रणाली के लिए काम करने का संकल्प लिया, जिसमें अधिक प्रतिनिधित्व, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ नवीनीकृत संस्थान और एक पुनर्गठित शासन व्यवस्था हो, जो 21 वीं सदी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाती हो। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और उसके अनुषंगी निकायों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढ़ांचे और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार और मजबूती लाने का आह्वान किया।

नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्धारक और प्रतिनिधित्व अंग के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका को मजबूत करके इसे सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक परिवर्तनकारी सुधार का संकल्प लिया ताकि इसे 21 वीं सदी की वास्तविकताओं और मांगों के अनुरूप बनाया जा सके, जिससे इसमें और अधिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता, कुशलता, प्रभावशीलता, लोकतांत्रिक मूल्य, जवाबदेही और पारदर्शिता लायी जा सके। उन्होंने आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और शांति व्यवस्था संबंधी आयोग को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेताओं ने पारदर्शिता, समान भौगोलिक वितरण, राष्ट्रीयताओं के रोटेशन और पदों को भरने में योग्यता और लैंगिक संतुलन के माध्यम से एक बेहतर प्रतिनिधित्व वाले संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के लिए प्रतिबद्धता जताई। नेताओं ने वैश्विक अभिशासन सुधार पर कार्रवाई के लिए जी20 आह्वान की भावना में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के साथ मिलकर काम करने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

नई दिल्ली में दिए गए अधिदेश के आधार पर, नेताओं ने बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों की दिशा में जी20 रोडमैप का समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों से जुड़े निर्णय लेने में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व और उनकी आवाज को सामने लाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

नेताओं ने विश्व व्यापार संगठन के कार्यों में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तन के प्रति अपना समर्थन दोहराया, ताकि एक नियम-आधारित, गैर-भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष, खुली, समावेशी, न्यायसंगत, टिकाऊ और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली सुनिश्चित की जा सके, जिसमें सभी सदस्यों के लिए एक सुचारू रूप से काम करने वाली विवाद निपटान प्रणाली सुलभ हो।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा इस प्रकार से मजबूत हुआ है कि जी-20 सदस्यों ने सुरक्षा परिषद की संरचना को विस्तृत करने का आह्वान किया, जिससे अफ्रीका, एशिया-प्रशांत और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले और बिना प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ सके।

*****